ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 179-181**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

डोनाल्ड ट्रम्प का द्वितीय कार्यकाल और भारत–अमेरिका सम्बन्धः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रोफे0 राकेश कुमार शुक्ल
राजनीति विज्ञान विभाग, के0 बी0 पी0 जी0 कालेज, मिर्जापुर (उ0प्र0) भारत

Received-15.07.2026, Revised-23.07.2026, Accepted-30.07.2026, **E-mail:rakeshshukla2795@gmail.com**

सारांशः ***यह शोध लेख डोनाल्ड ट्रम्प के द्वितीय कार्यकाल (20 जनवरी 2025 से प्रारंभ) के परिप्रेक्ष्य में भारत–अमेरिका सम्बन्धों के बहुआयामी स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। ट्रम्प 2.0 का विश्वदृष्टिकोण प्रथम कार्यकाल की तुलना में अधिक दृढ़, लेन–देनवादी (transactional) और 'अमेरिका फर्स्ट' की सभ्यतागत यथार्थवादी व्याख्या पर आधारित है। इस पृष्ठभूमि में भारत–अमेरिका सम्बन्धों ने एक विरोधाभासी यात्रा तय की है– एक ओर रणनीतिक अपरिहार्यता और व्यक्तिगत रसायन विज्ञान ने सम्बन्धों को संस्थागत ऊंचाई दी है, तो दूसरी ओर टैरिफ युद्ध, आव्रजन पर कठोरता और भू–राजनीतिक स्वायत्तता के प्रश्नों ने 25 वर्षों में बनी सद्भावना को चुनौती दी है।***

फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा और US-India COMPACT (Catalysing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce and Technology) की शुरुआत इस कार्यकाल का आधार स्तंभ बनी। 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य, F–35 जैसे उन्नत रक्षा प्लेटफार्म की पेशकश, और ऊर्जा साझेदारी इसके सकारात्मक पक्ष हैं। वहीं 50% तक टैरिफ की धमकी, H-1B वीज़ा पर कार्रवाई, भारत–पाक संघर्ष में मध्यस्थता के दावे और कृषि क्षेत्र को खोलने के दबाव ने सम्बन्धों में तनाव पैदा किया। यह लेख तर्क देता है कि ट्रम्प 2.0 में भारत–अमेरिका सम्बन्ध 'रणनीतिक अभिसरण और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच प्रबंधन' के नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं।

कुंजीभूत शब्द– ट्रम्प 2.0, भारत–अमेरिका , COMPACT, अमेरिका फर्स्ट, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार युद्ध, क्वाड, रक्षा सहयोग।

प्रस्तावना– डोनाल्ड जे. ट्रम्प का 47वें राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल अमेरिकी राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना है। वे ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो गैर–लगातार कार्यकाल जीते हैं, और 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद लोकप्रिय वोट जीतने वाले पहले रिपब्लिकन हैं। उनके प्रथम कार्यकाल (2017–2021) में भारत–अमेरिका सम्बन्धों ने उल्लेखनीय प्रगति देखी थीः क्वाड का पुनरुद्धार, भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा और STA–1 (Strategic Trade Authorization–1) के तहत उन्नत तकनीक तक पहुँच।

द्वितीय कार्यकाल की शुरुआत भी आशावाद के साथ हुई। प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प के शपथ ग्रहण के कुछ हफ्तों के भीतर ही उनसे मिलने वाले चौथे विश्व नेता थे, इजरायल, जापान और जॉर्डन के बाद। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 'प्रिय मित्र' को बधाई देते हुए निकटता से काम करने की आशा व्यक्त की, परन्तु, ट्रम्प 2.0 का चरित्र अधिक आक्रामक और परिणामोन्मुख है। उनका प्रशासन टैरिफ को केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि भू–राजनीतिक दबाव के उपकरण के रूप में देखता है। इस द्वंद्वात्मकता में भारत की स्थिति अद्वितीय है– अमेरिका के लिए चीन के प्रतिसंतुलन के रूप में अपरिहार्य, परन्तु अमेरिका के बाजार के लिए एक 'टैरिफ किंग' और 'कठिन वार्ताकार' के रूप में देखा जाने वाला देश।

डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2025 में शुरू हुए दूसरे कार्यकाल ने भारत–अमेरिका संबंधों के सामने एक दिलचस्प स्थिति पैदा की है। एक ओर, दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, इंडो–पैसिफिक, क्वाड और चीन के संदर्भ में रणनीतिक अभिसरण पहले से अधिक गहरा हुआ है; दूसरी ओर, ट्रंप की "America First", पारस्परिक व्यापार, शुल्क और लेन–देन आधारित कूटनीति भारत के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। फरवरी 2025 में ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने U.S.&India COMPACT तथा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य घोषित किया था।

शोध उद्देश्य और पद्धति– इस लेख के उद्देश्य हैं:

1. ट्रम्प के द्वितीय कार्यकाल की विदेश नीति के वैचारिक आधार को समझना।
2. फरवरी 2025 के ब्डब्च्।ब्ज समझौते के प्रमुख स्तंभों का मूल्यांकन करना।
3. व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और प्रवासी–आधारित आयामों में प्रगति और गतिरोध का विश्लेषण करना।
4. 2025–26 के घटनाक्रम के आधार पर भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना।

यह अध्ययन वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस (CRS), कार्नेगी, भारतीय विदेश मंत्रालय के वक्तव्य और प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स का उपयोग किया गया है।

ट्रम्प 2.0 की विदेश नीति का वैचारिक ढाँचाः भारत के लिए निहितार्थ– ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल को तीन सिद्धांतों से समझा जा सकता हैः

क. सभ्यतागत यथार्थवाद (Civilizational Realism): ट्रम्प प्रशासन दुनिया को उदार बनाम सत्तावादी के बजाय सभ्यताओं और शक्ति केन्द्रों के रूप में देखता है। इस दृष्टिकोण में भारत एक प्राचीन सभ्यता और हिंद–प्रशांत में प्राकृतिक शक्ति के रूप में अपरिहार्य है। यह बताता है कि क्यों ट्रम्प भारत को चीन के खिलाफ 'रणनीतिक शर्त' के रूप में देखते हैं, न कि केवल बाजार के रूप में।

ख. लेन–देनवादः हर सम्बन्ध का मूल्यांकन व्यापार घाटे और तत्काल लाभ से होता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई का यह कथन कि प्रशासन 'अमेरिकियों और अमेरिका फर्स्ट को प्राथमिकता देने वाला ऐतिहासिक व्यापार सौदा' चाहता है, इसी मानसिकता को दर्शाता है।

ग. टैरिफ एज हथियारः ट्रम्प ने 2025 में भारत सहित दर्जनों देशों पर जबरन श्रम से बने सामानों के आरोप में 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव और बाद में भारत पर 50% तक टैरिफ की धमकी दी। अमेरिकी कांग्रेस की ब्वै रिपोर्ट ने भी चेतावनी दी कि ट्रम्प की टैरिफ नीति, मई में भारत–पाक संघर्ष को समाप्त करने के दावे और पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ व्हाइट हाउस में लंच ने 25 वर्षों में बने सम्बन्धों को अस्थिर किया है।

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

व्यापार और अर्थव्यवस्था– 'मिशन 500 बिलियन' बनाम टैरिफ युद्धः 13 फरवरी 2025 को मोदी–ट्रम्प शिखर वार्ता का सबसे बड़ा परिणाम US & India COMPACT का शुभारंभ था। COMPACT के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। सकारात्मक यह रहा कि अमेरिका भारत के तेल और गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने को तैयार हुआ। ट्रम्प ने कहा, "भारत को बहुत सारे तेल और गैस की खरीद करनी होगी... उनके पास इसकी जरूरत है और हमारे पास यह है।" भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि वार्ताएं 'अच्छी तरह आगे बढ़ रही हैं' और फ्रेमवर्क डील तैयार है। रिपोर्टों के अनुसार अंतिम समझौते में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति बनी, और नकारात्मक यह रहा कि वार्ताएं कृषि और डेयरी क्षेत्र को लेकर अटकीं। भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे कृषि पर 'रेड लाइन' से समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद सत्र के दौरान समझौते की घोषणा और किसानों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। अमेरिकी पक्ष ने भारत को धीमा और नौकरशाही वाला वार्ताकार बताया। एक वरिष्ठ भारतीय–अमेरिकी सर्वेक्षण (IAAS 2026) में 71% भारतीय–अमेरिकियों ने ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के प्रदर्शन को अस्वीकार किया, जो डायस्पोरा में चिंता को दर्शाता है।

रक्षा और रणनीतिक साझेदारी– रक्षा सहयोग ट्रम्प 2.0 में भी सबसे स्थिर स्तंभ रहा है। COMPACT के तहत रक्षा को पहला स्तंभ बनाया गया। ट्रम्प ने भारत को F–35 स्टील्थ लड़ाकू विमान की पेशकश की, जो अब तक केवल नाटो और प्रमुख सहयोगियों तक सीमित था। प्रमुख रक्षा समझौतेः 2025 को अमेरिकी दूतावास ने रक्षा समझौतों के वर्ष के रूप में चिह्नित किया, जिसमें समुद्री सुरक्षा और सह–उत्पादन पर जोर रहा। भारत में रक्षा निर्माण व भारत के रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी आई है, जहाँ सरकार के 'मेक इन इंडिया' पुश से समेकन बढ़ा है। हालाँकि, पाकिस्तान के प्रति ट्रम्प के नरम रुख ने भारत में निराशा पैदा की, जिससे सामरिक विश्वास को झटका लगा।

प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष– COMPACT का दूसरा और तीसरा स्तंभ– Accelerated Commerce and Technology अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी में सेमीकंडक्टर, AI, क्वांटम और 5G-6G में सहयोग गहरा हुआ। दोनों नेताओं ने 'विस्तृत होती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग' पर विचारों का आदान–प्रदान किया। ऊर्जा क्षेत्र में ट्रम्प ने ऐतिहासिक व्यापार सौदों के साथ अमेरिका के कोयला निर्यात को नाटकीय रूप से बढ़ाने की बात कही, जिसमें भारत भी शामिल है। साथ ही असैन्य परमाणु सहयोग में अमेरिकी डिज़ाइन वाले रिएक्टरों के भारत में निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सहमति बनी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, NISAR (NASA & ISRO Synthetic Aperture Radar) मिशन 2025 में सम्बन्धों की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में भी उभरा है।

आव्रजन और मानव संबंध– 1B वीज़ा पर कार्रवाई और अवैध आव्रजन पर कठोरता ने भारतीय पेशेवर वर्ग और छात्रों को सीधे प्रभावित किया है। 2025 को भारतीय विदेश नीति के लिए "H&1B कार्रवाई और टैरिफ" के वर्ष के रूप में याद किया गया। यह मुद्दा घरेलू राजनीति में भी संवेदनशील बन गया है, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लाखों भारतीय अमेरिका में शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। H&1B वीज़ा भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए विशेष महत्व रखता है।

भू–राजनीतिः क्वाड, चीन और रूस– क्वाड ट्रम्प में भी जीवित रहा, परन्तु इसकी प्राथमिकता व्यापारिक हितों के अधीन हो गई। भारत की रूस के साथ 'दोस्ती' को लेकर पश्चिम की चिंता बरकरार रही। ट्रम्प प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से भारत–रूस संबंधों पर कम टिप्पणी की, लेकिन निजी तौर पर ऊर्जा खरीद पर दबाव बनाए रखा। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए, अमेरिका के साथ COMPACT और रूस के साथ रक्षा आपूर्ति दोनों को संतुलित करने की नीति जारी रखी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, ट्रम्प के दूसरे कैलेंडर वर्ष में प्रवेश करते ही भारत–अमेरिका कूटनीति 'कठिन परिश्रम से प्राप्त लाभ, व्यापार पर तीखे मतभेद और सतर्क हेजिंग' के बहीखाते जैसी लगती है।

डोनाल्ड ट्रम्प का यह कार्यकाल भारत–अमेरिका सम्बन्धों के लिए 'परिपक्वता की परीक्षा' है। पहला दशक (2000–2020) सम्बन्धों को बनाने का था, दूसरा दशक (2020–2030) उन्हें प्रबंधित करने का है। भारत–अमेरिका संबंधों पर द्वितीय कार्यकाल का प्रभावित क्षेत्र निम्न हैः भारत अमेरिका का प्रमुख रक्षा सहयोग साझेदार बन चुका है, इसके साथ ही संभावित सहयोग के रुप में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन, ड्रोन तकनीक, आधुनिक लड़ाकू प्रणालियाँ, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष रक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि है।

हिंद–प्रशांत रणनीति के क्षेत्र में भारत और अमेरिका दोनों स्वतंत्र, मुक्त एवं नियम–आधारित हिंद–प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण दोनों देशों का सामरिक सहयोग और अधिक मजबूत हुआ है। QUAD की भूमिका में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का QUAD समूह हिंद–प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। क्वाड के प्रमुख उद्देश्य हैः समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य सहयोग, उभरती प्रौद्योगिकियाँ।

चीन कारक– चीन का आर्थिक और सैन्य विस्तार भारत और अमेरिका के बीच सामरिक निकटता का एक प्रमुख कारण है। हालाँकि भारत चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ रक्षा एवं तकनीकी सहयोग भी बढ़ा रहा है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण है।

व्यापार एवं आर्थिक संबंध– भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध पिछले दो दशकों में निरंतर मजबूत हुए हैं। अमेरिका भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि उद्योग तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। "America First" नीति के अंतर्गत अमेरिकी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने तथा व्यापार घाटे को कम करने पर विशेष बल दिया गया। इस कारण भारत सहित अनेक देशों के साथ व्यापारिक वार्ताओं में पारस्परिक बाजार पहुँच (Market Access), आयात शुल्क (Tariffs) तथा गैर–शुल्क बाधाओं पर चर्चा तेज हुई। भारत के लिए अमेरिका निर्यात का एक बड़ा बाजार है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ, दवाइयाँ, वस्त्र, रत्न एवं आभूषण तथा इंजीनियरिंग उत्पाद भारतीय निर्यात के प्रमुख क्षेत्र हैं। दूसरी ओर भारत अमेरिका से रक्षा उपकरण, विमान, ऊर्जा उत्पाद, उच्च प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक मशीनरी का आयात करता है।

शुल्क (Tariff) एवं व्यापारिक चुनौतियाँ– ट्रम्प प्रशासन व्यापारिक संबंधों में पारस्परिकता (Reciprocity) पर बल देता है। इसी कारण निम्नलिखित विषयों पर समय–समय पर मतभेद उभरते हैंः भारतीय कृषि उत्पादों की बाजार पहुँच, चिकित्सा उपकरणों की

मूल्य निर्धारण नीति, इस्पात एवं एल्युमिनियम पर शुल्क, डिजिटल व्यापार, ई–कॉमर्स नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), फिर भी दोनों देश व्यापार समझौते के माध्यम से इन मतभेदों का समाधान खोजने का प्रयास करते रहे हैं।

ट्रम्प प्रशासन ने रोजगार सुरक्षा, वीज़ा नियमों की समीक्षा, अवैध प्रवास पर नियंत्रण, जैसी नीतियों पर बल दिया। इससे भारतीय आईटी कंपनियों तथा पेशेवरों पर कुछ प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, उद्यमियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। ऊर्जा सहयोग, भारत–अमेरिका संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं: एलएनजी (Liquefied Natural Gas), कच्चा तेल, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के विविधीकरण की नीति के अंतर्गत अमेरिका को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार के रूप में देखता है।

प्रौद्योगिकी एवं नवाचार– ट्रम्प के द्वितीय कार्यकाल में उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत और अमेरिका निम्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि, शिक्षा, प्रशासन में AI आधारित सहयोग।
- सेमीकंडक्टर, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका सेमीकंडक्टर निर्माण एवं अनुसंधान में सहयोग बढ़ा रहे हैं।
- साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा तथा साइबर अपराधों की रोकथाम दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है।
- अंतरिक्ष सहयोग, ISRO और NASA के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान, उपग्रह प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।

रक्षा एवं सामरिक सहयोग के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग वर्तमान समय में अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच चुका है। इसके अलावा मुख्य क्षेत्र, संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, रक्षा अनुसंधान, रक्षा उत्पादन, आधुनिक ड्रोन तकनीक, मिसाइल रक्षा, खुफिया सहयोग भी है। दोनों देशों के बीच हुए प्रमुख समझौते: LEMOA, COMCASA, BECA ने रक्षा सहयोग को नई गति प्रदान की है। आतंकवाद–रोधी सहयोग ने भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र: खुफिया जानकारी का आदान–प्रदान, आतंकवादी वित्तपोषण पर रोक, संयुक्त प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग आदि।

चीन और हिंद–प्रशांत का प्रभाव– चीन की बढ़ती सैन्य एवं आर्थिक शक्ति भारत और अमेरिका दोनों के लिए रणनीतिक चुनौती है। विशेष रूप से: दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरू मध्य, भारत–चीन सीमा, हिंद महासागर आदि इन क्षेत्रों में चीन की सक्रियता ने दोनों देशों को सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में कोविड–19 महामारी तथा भू–राजनीतिक तनाव के बाद वैश्विक उद्योगों ने चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई।

भारत विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, औषधि उद्योग में वैश्विक निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका इस प्रक्रिया में भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखता है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, भारत की विदेश नीति का आधार पर रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) है। भारत, अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग, रूस से रक्षा खरीद, यूरोप के साथ तकनीकी सहयोग, पश्चिम एशिया के साथ ऊर्जा संबंध बनाए रखना और चीन के साथ आवश्यक व्यापारिक संबंध भी बनाए रखना, यही संतुलन भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता है।

निष्कर्ष– इससे तीन महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं कि व्यक्तिगत रसायन विज्ञान पर्याप्त नहीं है। मोदी–ट्रम्प की व्यक्तिगत निकटता ने COMPACT जैसी पहल को गति दी, लेकिन संस्थागत मतभेदों को रोक नहीं सकी। भारत का 'अडिग' रुख ने 2025 में जल्दबाजी में खराब सौदा करने से इनकार कर दिया, यह दिखाते हुए कि वह अब 'बड़ा बाजार' नहीं, बल्कि 'बड़ा सौदेबाज' है। 'भारत ने 3 प्रमुख मांगों पर दृढ़ रुख अपनाया' वाली रणनीति इसी का प्रमाण है। भविष्य का मॉडल – चयनात्मक संरेखण स्वरुप में भारत, अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ तकनीक और रक्षा में गहराई से जुड़ेगा, लेकिन व्यापार और रूस के मामले में स्वायत्तता बनाए रखेगा। ट्रम्प प्रशासन को भी समझना होगा कि भारत को 'सहयोगी' के रूप में नहीं, बल्कि 'स्वतंत्र ध्रुव' के रूप में देखना अधिक लाभदायक है। 21वीं सदी में भारत–अमेरिका संबंध अब केवल द्विपक्षीय संबंध नहीं रह गए हैं; वे इंडो–पैसिफिक शक्ति–संतुलन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और चीन के उदय से जुड़े हुए हैं।

अंततः, ट्रम्प ने भारत को एक कठिन परन्तु आवश्यक सबक सिखाया है। रणनीतिक साझेदारी भावना से नहीं, बल्कि निरन्तर सौदेबाजी और हितों के स्पष्ट प्रबंधन से चलती है। डोनाल्ड ट्रम्प का द्वितीय कार्यकाल और भारत–अमेरिका सम्बन्ध एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Business Standard- (2025). Trump Inauguration 2025 and US&India relations.
2. The Indian Eye- (2025). PM Modi congratulates dear friend Trump.
3. US Embassy in India. (2025). Key Moments in India&US Relations 2025: Trump&Modi talks, COMPACT launch.
4. Ministry of External Affairs, India. (2025). Press Statements on India&US COMPACT review.
5. Carnegie Endowment for International Peace. (2025). Trump 2.0: Navigating India&US Relationship.
6. Congressional Research Service (CRS), US Congress. (2025). Report on India&US ties under Trump second term.
7. Indian Express. (2026). One year of India and Trump 2.0: A balance sheet.

*****